

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत)

अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सोसायटी का उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संपरिवर्धित करना है या ऐसी संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जो पंजीकृत की गई है ।

क. 1- नाम, पता, कार्यक्षेत्र-

1	समिति का नाम-	
2	समिति का पंजीकृत पता- (यदि शाखाएं हों तो उसका विवरण)	
3	समिति का कार्यक्षेत्र-	

समिति पर भारत सरकार द्वारा प्रभावशील किये गये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधान लागू होंगे ।

क. 2-परिभाषाएं-

1	अधिनियम-	से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है ।
2	सहकारी वर्ष-	से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष है ।
3	पंजीयक-	से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वर्णित पंजीयक, अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक से है ।
4	कार्यक्षेत्र-	से तात्पर्य वह क्षेत्र है जहां कि सदस्य समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं ।
5	उपविधि-	से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 6 के निर्धारित विषयों के अंतर्गत तैयार की गई उपविधि से है जो सदस्यों द्वारा मान्य की जाकर पंजीयक से अनुमोदित है । इसमें समय-समय पर कराये गये संशोधन भी मान्य होंगे ।
6	संचालक मंडल-	से तात्पर्य अधिनियम की धारा 48 के अधीन शासी निकाय या प्रबंधन से है जो सोसायटी के कार्यकलापों का प्रबंधन तथा संचालन एवं नियंत्रण करेगा ।

7	वित्तदायी संस्था—	से तात्पर्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर की सहकारी संस्था या केंद्र या राज्य सरकार या जिला/राज्य स्तर की बैंक जो सहकारी सोसायटी को या सदस्य को वित्तीय सहायता, अग्रिम या उधार दे ।
8	सदस्य—	से तात्पर्य सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति व संस्था की उपविधि को स्वीकार कर अधिनियम/नियम एवं उपविधि के अधीन सदस्यता प्रदान करने का आवेदन किया हो व जिसे मान्य किया है । सदस्यता के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अंशपूजी में किया गया योगदान भी सम्मिलित है ।
9	नाममात्र का सदस्य—	से तात्पर्य अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत ऐसा सदस्य जिसके द्वारा सदस्यता के रूप में अंश क़य किया गया है किन्तु उसे सोसायटी के प्रबंध या लाभांश की अधिकारिता नहीं होगी और सोसायटी के परिसमापन की दशा में लिये गये अंश को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।
10	कार्यपालक मजिस्ट्रेट—	से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन नियुक्त अधिकारी ।
11	अधिकारी—	से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो सोसायटी की उपविधि के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त किया गया है । इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालक, कोषाध्यक्ष सम्मिलित हैं । इसमें सोसायटी से कारोबार के संबंध में निर्देश देने, कार्य करने, कार्यसंचालन में सहयोग देने के लिये अधिनियम/नियम/ उपविधि के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचित किये गये या नियुक्त किये गये व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ।
12	विनिर्दिष्ट पद—	से तात्पर्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से है ।
13	सेवानियम—	से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 55 (1) के अंतर्गत नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारियों के कार्य संचालन के लिये बनायी गयी नियमावली से है ।
14	संपरीक्षक—	से तात्पर्य सहकारी सोसायटी के लेखाओं के संपरीक्षण के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति या सनदी लेखापाल या सनदी लेखापाल फर्म से है ।
15	लाभांश—	से तात्पर्य सोसायटी के लाभों में से सदस्य द्वारा धारित किये गये पूर्ण प्रदत्त अंश के अनुपात में निर्धारित राशि से है ।
16	लोकसेवक—	से तात्पर्य ऐसा प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति जो सहकारी सोसायटी का अधिकारी एवं कर्मचारी है तथा जो अधिनियम/नियम/उपविधि के अधीन प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत कार्य किये जाने के लिये अधिकृत किया गया है, वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोकसेवक समझा जाएगा ।

17	प्रमाणीकरण पध्दति विवरण	से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन पध्दतियों को विनिर्दिष्ट करने के लिये जारी किया गया विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र जारी करने में प्रयोग करता है ।
18	कंप्यूटर	से ऐसी इलेक्ट्रानिक, चुम्बकीय, प्रकाशीय या अन्य द्रुत डाटा संसाधन युक्ति या प्रणाली अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रानिक चुम्बकीय या प्रकाशीय तरंगों के अभिचालनों द्वारा तर्कसंगत, अंकगणीतीय और स्मृतिफलन के रूप में कार्य करता है और इसके अंतर्गत सभी निवेश, उत्पाद, प्रक्रमण, भंडारण, कंप्यूटर साफटवेयर या संचार सुविधाएं भी हैं जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर से संयोजित या संबंधित होती हैं:- अ) "कंप्यूटर नेटवर्क" से— 1- उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, भौमिक लाइन या अन्य संचार मीडियो के उपयोग और 2- दो या अधिक अंतःसंबद्ध कंप्यूटरों से मिलकर बने टर्मिनलों या किसी सम्मिश्र, चाहे अंतःसंबंध निरंतर रखा जाता है या नहीं के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटरों का अंतःसंबंध अभिप्रेत है ।
19	कंप्यूटर साधन	से कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या साफटवेयर अभिप्रेत है ।
20	कंप्यूटर प्रणाली	से निवेश और निर्गम सहायक युक्तियों सहित और ऐसे केलकुलेटरों को छोड़कर जो क्रमादेश्य नहीं है और जो बाह्य फाइलों के साथ संयोजन में उपयोग में नहीं आ सकते ऐसी युक्ति या युक्तियों का संग्रह अभिप्रेत है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रानिक अनुदेश, निवेश डाटा और निर्गम डाटा भरे गये हैं जो तर्क, अंकगणीतीय , डाटा भंडारण और पुनः प्राप्ति, संचार नियंत्रण और अन्य कृत्य करती हैं ।
21	साइबर अपील प्राधिकरण	से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000के अंतर्गत धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित साइबर विनियमन अपील अधिकरण अभिप्रेत है ।
22	डाटा	से सूचना, जानकारी, तथ्यों, संकल्पनाओं या अनुदेशों का निरूपण अभिप्रेत है जिन्हें एक निश्चित रीति से तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है और जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किये जाने के लिये आशयित है, संसाधित किया जा रहा है या संसाधित किया गया है और जो किसी रूप में (जिसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रिंट आउट, चुम्बकीय या प्रकाशीय भंडारण मीडिया, छिद्रित कार्ड, छिद्रित टेप हैं) या कंप्यूटर की स्मृति में आंतरिक रूप से भंडारित हो सकता है ।
23	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख	से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप या माइक्रो रूप या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा, भंडारित, प्राप्त या प्रेषित प्रतिबिंब या ध्वनि अभिप्रेत है ।

24	सूचना	के अंतर्गत डाटा, पाठ, प्रतिबिंब, ध्वनि, वाणी, कोड, कंप्यूटर कार्यक्रम, साफ्टवेयर और डाटा संचय या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मिका भी आती है ।
25	अनुज्ञप्ति	से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 24 के अधीन किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ।
26	प्रवर्तक	से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजता है, उसका उत्पादन, भंडारण करता है या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित करता है अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भिजवाता है, उसका उत्पादन, भंडारण कराता है या किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित कराता है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है ।
27		पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं उसके अधीन बनाये गये ई-अपशिष्ट(प्रबंध एवं हथालना) नियम-2011 के अंतर्गत ई-वेस्ट के संग्रहण, भंजन(नष्ट करना) व पुनःचक्रण(रीसाइकल) की सभी परिभाषा इसके अधीन होगी ।

सहकारी अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व अन्य प्रभावशील अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई हैं उससे तात्पर्य होगा ।

क. 3 उद्देश्य—

समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

1		सूचना प्रौद्योगिकी किसानों, सहकारी समितियों, शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराना ।
2		सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद विक्रय करने के लिये शासन की नीति, विभिन्न मंडियों के भाव आदि उपलब्ध कराना ।
3		सहकारी संस्थाओं के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करना, उनके कार्यों में नवीनतम एवं अद्यतन विधियां एवं कार्यप्रणाली प्रस्तुत करना ।
4		सहकारी समितियों एवं उनसे लाभांविता होने वाले सदस्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लेखांकन व समितियों से संबंधित नवीन नियम आदि की जानकारी उपलब्ध कराना ।
5		संस्था के लेखा संधारण के लिये प्रोग्राम बनाना ।
6		केन्द्र, राज्य, अर्धशासकीय एवं सहकारी क्षेत्र के लिये सॉफ्टवेयर तैयार करना, उसका परिचालन करना तथा मरम्मत आदि की सुविधा उपलब्ध कराना ।
7		ग्रामीण क्षेत्र की समितियों तथा उनके सदस्य जैसे— प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक दुग्ध समिति, पशुपालन समिति से संबंधित जानकारी जैसे मौसम की जानकारी, उसके परिणामस्वरूप होने वाले रोग तथा उनके उपचार तथा रोगों की रोकथाम, कीटनाशक, विभिन्न प्रकार के बीज, आधुनिक संयंत्रों के उपयोग, उनकी उपलब्धता की जानकारी देना ।
8		समिति द्वारा स्वयं या संबंधित संस्था की मांग पर कम्युनिटी रेडियो, सूचना केन्द्र स्थापित करना ।

9		ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराना ।
10		कृषि और उससे जुड़े हुए व्यवसायों में मशीनीकरण के माध्यम से लागत कम करने के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।
11		ग्रामीण क्षेत्र में कियोस्क व अन्य माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना ।
12		सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देना, तकनीक से अवगत कराना तथा इससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान करना ।
13		कम्प्यूटर व उससे संबंधित उपकरण उपलब्ध कराना ।
14		भारत सरकार के ई-अपशिष्ट(प्रबंध और हथालना) नियम 2011 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर व रेडियोधर्मी अपशिष्ट, बैटरी आदि जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त कर अपशिष्ट को संबंधित संस्थाओं से क्य करना व उसका पुनःचक्रण (रीसाइकल) या नष्ट करना, जैसा कि निर्देशित किया गया है ।
15		अन्य ऐसे समस्त कार्य करना जो समिति के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये आवश्यक हों ।
		– प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कार्य किये जाने हेतु अनुज्ञप्ति (लायसेंस) आदि लिया जाकर कार्य किया जाएगा ।
		– संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई तकनीक सुविधा व ज्ञान के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत समस्त प्रकार के लायसेंस प्राप्त करने के पश्चात संबंधित संस्था सेवा प्राप्त करेगी व उसका उपयोग करेगी जिसके लिये प्रावधान किया गया है ।

क. 4 सेवा जो सदस्यों को प्रदान की जावेगी –

1		केंद्र, राज्य, अर्ध शासकीय संस्था तथा सहकारी क्षेत्र के कार्यालय में कम्प्यूटर सामग्री उपलब्ध कराना, मरम्मत करना, साफ्टवेयर तैयार करके देना, उसके परिचालन में सहयोग प्रदान करना ।
2		सहकारी क्षेत्र व अन्य प्रकार की गठित समितियों के सदस्यों को सूचना तकनीक का ज्ञान देना एवं उसके उपकरण उपलब्ध कराना ।
3		सहकारी क्षेत्र की ग्रामीण समितियों जैसे, प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक दुग्ध समिति, पशुपालन समिति आदि के सदस्यों को उनके कार्य संबंधी अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराना एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्य को आधुनिक तरीके से किये जाने का प्रशिक्षण देना व उनके कार्य में सहयोग प्रदान करना ।
4		ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा उससे आधारित पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, जैविक खेती एवं लागत कम करने के लिये मशीनीकरण संबंधी अनुसंधान करना, प्रशिक्षण देना । मशीनीकरण किये जाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग देना ।
5		ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण कराया जाना, उसका साफ्टवेयर तैयार करना, कम्प्यूटर उपलब्ध कराना उनकी मरम्मत करना एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ।

6		विभिन्न क्षेत्रों में ई-टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया की जाती है इस हेतु सहकारी समिति, उसके सदस्य एवं अन्य समुदाय को सेवा उपलब्ध कराना ।
7		समिति अपने सदस्यों, शीर्ष संस्थाओं के लिये इलेक्ट्रॉनिक डाटा के आदान-प्रदान और संसूचना को जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के अंतर्गत आती है, निष्पादित करेगी ।
8		समिति कम्प्यूटर नेटवर्क क्षेत्र के अंतर्गत भी कार्य करेगी ।
9		सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संबंधी जो प्रावधान किये गये हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा का आदान-प्रदान तथा संसूचना का आदान प्रदान किये जाने हेतु जो प्रावधान किये गये हैं, जिनमें भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंक बही साक्ष्य अधिनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत जो नियम एवं प्रावधान प्रभावशील किये गये हैं के अंतर्गत कार्यवाही करना ।
10		सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उपयोग किये जाने वाले सभी उपस्कर, मशीन उनके पार्ट्स अधिकृत संग्रहकर्ता के रूप में लायसेंस प्राप्त कर संग्रहण विनिष्ठीकरण तथा रीसाइकल की सुविधा उपलब्ध कराना ।

क. 5—सदस्यता:—

व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे—

1		व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो ।
2		व्यक्ति भारतीय संविदा(अनुबंध) अधिनियम 1872 की धारा-11 के अंतर्गत संविदा करने में सक्षम हो ।
3		अन्य कोई समिति ।
4		प्रभावशील विधि के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकृत/स्थापित/गठित फर्म/कंपनी/निगमित निकाय ।
5		राज्य सरकार ।
6		शासन द्वारा किसी आदेश विशेष से पंजीकृत की गई कोई समिति ।

क. 6—सदस्यता का प्रकार:—

1		वह सदस्य बन सकेगा कम्प्यूटर एवं इससे संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखता हो/डिग्री धारक हा , उसका निर्माणकर्ता या विक्रेता हो, संबंधित क्षेत्र का प्रशिक्षणदाता हो ।
2		सहकारी संस्था के उददेश्यों के निर्वहन में जो सहकारी समिति के माध्यम से अपना व्यवसाय कर रहा हो । समिति को व्यवसाय करने में सहयोगी हो वह एक अंश क्य कर नाममात्र का सदस्य बन सकता है ।

3		वे व्यक्ति भी सदस्य हो सकेंगे जिन्हें नामांकित किया गया है और वे सदस्य होना चाहते हैं ।
4		ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी नैतिक/आपराधिक रूप से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और वह अवधि को 5 वर्ष व्यतीत हो गये हैं वे सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता की स्थिति में उसे कार्य करने के लिये किसी विधि या न्यायालयीन आदेश से प्रतिबंधित किया गया है वे सदस्य नहीं हो सकेंगे और वह व्यक्ति भी सदस्य नहीं हो सकेगा जिसे शासकीय या नगर निकाय, मंडी, सहकारी संस्था या अन्य कोई सार्वजनिक उपक्रम से पदच्युत कर दिया हो ।

क. 7—सदस्यता प्रदान करना:—

1		संस्था के पंजीयन के समय पंजीयन प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र में संस्था का आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, उस आवेदन का प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष/कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार किया जावेगा ।
2		संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण जानकारी देते हुए अध्यक्ष को संबोधित आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जो प्रबंधक के द्वारा प्राप्त कर संचालक मंडल की बैठक में रख कर निर्णय लिया जाए कि उसका आवेदन मान्य/अमान्य किया गया है । संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किये जाने की स्थिति में अनिवार्यतः 15 दिवस की अवधि में योग्य माध्यम से अवगत कराया जावेगा एवं जिस माध्यम से उसे अवगत कराया गया है उस संबंधी कार्यवाही रेकार्ड में सुरक्षित रखी जावेगी ।
3		सदस्यता के लिये एक पंजी संधारित की जावेगी जिसमें सदस्यता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन का ब्यौरा होगा । सदस्यता के आवेदन को स्वीकार किये जाने की स्थिति में संबंधित आवेदक को सूचित कर अंश पूंजी एवं प्रवेश शुल्क से अवगत कराया जावेगा । मांग की गई राशि जमा किये जाने की स्थिति में सदस्य का नाम सदस्यता पंजी में अंकित कर सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति एवं अंश प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।
4		सदस्यता पंजी में प्रविष्टि किये जाने के समय सदस्य को आहूत कर उसके हस्ताक्षर लिये जाएंगे तथा नामांकित/वारिस की जानकारी ली जाएगी । इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य की मांग भी की जा सकती है ।

क. 8—सदस्यता की समाप्ति:—

1		कोई भी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने के उपरांत सदस्यता प्रदान कर दी गई हो उसके पश्चात अधिनियम/नियम एवं उपविधि की निर्दिष्ट अर्हता नहीं रखता हो तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।
---	--	---

क. 9—सदस्यता वापस लेना:—

1		अधिनियम एवं नियमों के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कोई सदस्य प्रक्रिया का पालन कर सदस्यता वापस ले सकेगा ।
2		सदस्यता वापस लेने की स्थिति में विधिक प्रावधान के अंतर्गत एक वर्ष तक सदस्य के रूप में बाध्यताओं की पूर्ति अपेक्षित रहेगी ।
3		सदस्यता वापस लेने की स्थिति में सदस्य की अंश राशि या सदस्यता हित किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा । इसके लिये एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई हो । इस संबंध में अधिनियम की धारा-25 अंशों या हितों के अंतरण पर निर्बंधन प्रभावशील होगा ।
4		सदस्य के द्वारा सदस्यता वापसी की स्थिति में सहकारी सोसायटी नियम-20 के प्रावधानों के अंतर्गत अंश का मूल्यांकन किया जाएगा । मूल्यांकन में यदि अंश का अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य हो तो अंकित मूल्य और उससे कम मूल्य है तो कम मूल्य दिया जाएगा ।

क. 10—सदस्यों का रजिस्टर:—

1		प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी एवं उसमें निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी—
	क—	प्रत्येक सदस्य का नाम, पता एवं उसकी उपजीविका,
	ख—	उस दशा में जहां कोई सोसायटी अंशपूंजी रखती है, के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश,
	ग—	वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया,
	घ—	ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

क. 11— अंशपूंजी:—

1	अधिकृत अंशपूंजी—	1—	एक अंश रु. 1000 /— का होगा यह.....अंशों में विभक्त होगा ।
2	प्रदत्त अंशपूंजी—	1—	प्रत्येक सदस्य को एक अंश लेना अनिवार्य होगा ।

		2-	कोई भी सदस्य सोसायटी की कुल अंशपूंजी के 1/5 या रू. 20000/- से अधिक के अंश या हित नहीं रखेगा । इस संबंध में राज्य शासन अधिसूचना जारी कर छूट प्रदान कर सकता है ।
		3-	प्रत्येक सदस्य को एक अंश की संपूर्ण राशि एक साथ जमा करानी होगी ।
		4-	सदस्यों को अंश प्रमाणपत्र दिये जाएंगे जिनमें एक से अधिक अंशों का समायोजन कर एक अंश प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है ।
		5-	अंश प्रमाणपत्र पर संस्था के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं संस्था की पदमुद्रा अंकित होना अनिवार्य है ।
		6-	सदस्य का अंश अंतरण अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत होगा ।
		7-	अंश की बिक्री, उपहार या अन्य किसी प्रकार का अंतरण नहीं होगा या अधिनियम/नियम की वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होगा ।
		8-	अंशपूंजी की वापसी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-17 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी एवं उसका मूल्यांकन नियम-20 के अंतर्गत होगा ।

क. 12-सदस्य का दायित्व:-

1		संस्था पर सदस्यों का दायित्व उसके अंश के मूल्यों का 10 गुना होगा । सदस्यों के दायित्व उस ऋण तथा अन्य संस्था पर अलग होंगे तथा समय दो वर्ष तक का होगा ।
---	--	---

क. 13-पूंजी एवं निधियां:-

संस्था द्वारा पूंजी एवं निधियां निम्नानुसार ली जाएंगी -

1		अंश विक्रय से
2		प्रवेश शुल्क से
3		अमानत जमा कराकर
4		अग्रिम धन जमा कराकर
5		अनुदान प्रदान कर

6		शुद्ध लाभ से निधियों का निर्माण कर
7		राज्य/केंद्र सरकार से अंशपूजी प्राप्त कर
8		शासन द्वारा या पंजीयक द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश या अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निधियों का निर्माण कर ।

क. 14—संचालक मंडल:—

1	क—	संचालक मंडल में 11(ग्यारह) निर्वाचित सदस्य होंगे । इन निर्वाचित सदस्यों के लिये संचालक मंडल द्वारा भौगोलिक आधार पर टेरिटरी निर्धारित की जाएगी ।
	ख—	प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पदेन सदस्य सचिव)
	ग—	पंजीयक के प्रतिनिधि के रूप में या शासन से संबंधित विभाग के संचालक – एक
	घ—	वित्तदायी संस्था से वित्त प्राप्त करने की स्थिति में— एक सदस्य
2		संचालक मंडल का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा ।
3		संचालक मंडल की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार बुलाई जाएगी और एक वर्ष में 4 बैठक होना आवश्यक है ।
4		संचालक मंडल की बैठक में गणपूर्ति संचालक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम आधे से अधिक पर होगी ।
5		संचालक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा एवं मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा ।
6		संचालक मंडल के सदस्यों से संबंधित यदि कोई विषय संचालक मंडल में विचार के लिये आता है तो उस विषय के विचारण में उस संचालक की सहभागिता नहीं होगी ।
7		किसी विषय विशेष पर निर्णय अत्यावश्यक है और ऐसे विषय को आगामी संचालक मंडल की बैठक तक स्थगित नहीं किया जा सकता है तो उस विषय पर भ्रमणशील प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया जावेगा और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर सहमति मानी जाएगी । यह कार्यवाही ऐसी मानी जाएगी जैसे कि संचालक मंडल की विधिवत बैठक बुलाई गई हो । आगामी संचालक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा ।
8		संचालक मंडल की बैठक की कार्यवाही विवरण पंजी में अंकित की जाएगी । उस पर अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर होंगे । कार्यवाही विवरण संचालक मंडल के प्रत्येक सदस्य को बैठक दिनांक से 30 दिन की अवधि में भेजी जाएगी ।

क. 15—संचालक मंडल के अधिकारः—

साधारण सभा के लिये सुरक्षित अधिकार—

अधिनियम/नियम एवं उपविधि के प्रतिबंधों के अधीन संचालक मंडल को संस्था के गठन/प्रबंधन के उद्देश्य से एवं कार्यों के निष्पादन के लिये समस्त अधिकार होंगे । विशेषकर निम्नानुसार होंगे –

1		सदस्यता स्वीकार एवं समाप्त करना
2		सभापति एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना
3		सभापति और पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और उन्हें पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना ।
		परन्तु उपयुक्त प्रयोजन के लिये होने वाले सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
4		संचालकों द्वारा दिये गये त्यागपत्रों पर निर्णय लेना ।
5		रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारीवृन्द की संख्या नियत करना ।
6		निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना—
	ए—	सदस्यों को सेवाएं देने के लिये संगठन एवं उपबंध करना
	बी—	रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारीवृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तें और कर्मचारीवृन्द से संबंधित अन्य विषय
	सी—	निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग
	डी—	लेखाओं के रखे जाने की रीति
	ई—	निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान
	एफ—	फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियों के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध ।

7		साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय योजना एवं बजट प्रस्तुत करना ।
8		संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना और
9		ऐसे अन्य समस्त कृत्य करना जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हैं । परन्तु सहकारी साख संरचना के कर्मचारीवृंद की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तों और कर्मचारीवृंद से संबंधित अन्य मामलों की नीतियां, राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार विरचित की जाएगी ।

क. 16—यात्रा भत्ता:—

1		संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित होने के लिये यात्रा भत्ता एवं मानदेय जो पंजीयक एवं आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है, के आधार पर दिया जाएगा ।
---	--	---

क. 17—संचालक की पात्रता:—

1		संचालक मंडल का सदस्य बने रहने के लिये म.प्र. सहकारी अधिनियम एवं नियम क्र. 44, 45 के प्रावधान के अंतर्गत पात्रता होगी । इसके अतिरिक्त संचालक निर्वाचन की 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक रहेगा ।
2		संचालक को निर्धारित किये गये अंश लेना अनिवार्य होंगे किन्तु किसी भी दशा में एक अंश से कम अंश नहीं होगा ।
3		संस्था में किसी भी प्रकार के पद पर नहीं होगा ।
4		केंद्र/राज्य सरकार या किसी भी सहकारी संस्था के कर्मचारी के रूप में बर्खास्त किया गया कर्मचारी/अधिकारी नहीं होगा ।
5		सहकारी अधिनियम/नियम के अधीन कर्तव्य एवं अधिकारों के निर्वहन, अपेक्षावान रजामंद नहीं होने के प्रावधानों की प्रभावशीलता के कारण भी संचालक की पात्रता नहीं रहेगी ।

क. 18—साधारण सभा के कार्य:—

साधारण सभा अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत प्रतिवर्ष सहकारी वर्ष समाप्त होने के 6 माह की अवधि में निम्नांकित विषय पर आहूत की जाएगी —

1		गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टी करना ।
2		संचालक मंडल के सदस्य का निर्वाचन यदि वह अपेक्षित हो गया है ।
3		संपरीक्षा रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई हो ।
4		शुद्ध लाभ यदि हुआ हो तो उसका व्ययन ।
5		अगले वर्ष के बजट की स्वीकृति ।
6		गत वर्ष के स्वीकृत बजट से अधिक हुए व्ययों की स्वीकृति ।
7		अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संचालक मंडल से प्राप्त पालन प्रतिवेदन ।
8		संचालक मंडल की बैठक एवं अन्य बैठकों में भाग लेने के लिये संचालक मंडल तथा चुने हुए प्रतिनिधियों के लिये दिये जाने वाले भत्ते एवं अन्य भुगतान का निर्धारण ।
9		क्रियाकलापों के कार्यक्रम का जो कि संचालक मंडल द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किया गया हो, अनुमोदन ।
10		उपविधियों में संशोधन ।
11		यदि किसी वर्ष में परिचालन घाटा हुआ हो तो इस घाटे के लिये संचालक मंडल द्वारा बताये गये कारणों का परीक्षण ।
12		आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति करना और पारिश्रमिक तय करना ।
13		अधिनियम/नियम एवं उपनियमों की परिसीमा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति द्वारा प्राप्त की जाने वाली अमानतों, ऋण एवं ऋणपत्रों की अधिकतम सीमा तथा ब्याज दरें निश्चित करना ।
14		संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत या नियमानुसार प्राप्त एवं अनुमत कोई अन्य विषय ।

क. 19—साधारण सभा :-

1		साधारण सभा संस्था की सर्वोच्च सभा है ।
2		साधारण सभा में राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित सदस्य एवं पदेन सदस्य भी होंगे ।
3		साधारण सभा प्रतिवर्ष सहकारी वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि में आहूत की जाएगी ।
4		साधारण सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में साधारण सभा में उपस्थित निर्वाचित सदस्य में से कोई सदस्य जिसका कि निर्णय आमसभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, अध्यक्षता की जाएगी ।
5		संचालक मंडल नहीं होने की स्थिति में साधारण सभा की अध्यक्षता प्रशासक द्वारा की जाएगी । इस संबंध में म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम-36 के प्रावधान लागू होंगे ।
6		साधारण सभा धारा-49 में वर्णित किये गये विषयों पर आहूत की जाएगी किन्तु विशिष्ट परिस्थिति में पंजीयक द्वारा निर्देशित किये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत विशेष साधारण सभा आहूत की जाएगी ।

क. 20—साधारण सभा की गणपूर्ति :-

1		साधारण सभा के लिये गणपूर्ति सभा का सूचनापत्र दिये जाने की दिनांक को कुल सदस्य या कुल सदस्य के 1/10 या 50 जो तीनों में से कम है, के द्वारा की जाएगी । इस संबंध में उपविधि में कोई भी प्रावधान होने पर भी गणपूर्ति के लिये यह मान्य होगा ।
2		साधारण सभा का कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा जबतक कि गणपूर्ति नहीं हो जाए ।
3		यदि आमसभा के लिये नियत किये गये समय से 1/2 घंटे के अंदर गणपूर्ति नहीं होती है तो आमसभा स्थगित की जाएगी और उसी दिनांक, समय एवं स्थान जैसा वह उदघोषित करें, तक के लिये स्थगित होगी और स्थगित की गई आमसभा में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी किन्तु उसमें उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाएगी जो कि सूचनापत्र में वर्णित किये गये थे ।

4		विशेष आमसभा रजिस्ट्रार स्वयं या सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 द्वारा अध्यापेक्षी किये जाने पर बुलाई जाएगी ।
5		विशेष आमसभा सदस्यों की मांग पर बुलाई जाने पर स्थगित नहीं की जाएगी ।

क. 21—साधारण सभा के कार्यक्रम :-

1		साधारण सभा की कार्यवाही के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये रखी गई पंजी में दर्ज किये जाएंगे । इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे ।
2		साधारण सभा या विशेष साधारण सभा का कार्यवृत्त ऐसी सभा होने के दिनांक से 30 दिन की समयावधि में प्रत्येक सदस्य को प्रेषित किया जाएगा ।

क. 22—निर्वाचन :-

1		संचालक मंडल के निर्वाचन के लिये म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अधिकृत तथा आदेशित किये गये निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाएगी ।
2		संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संचालक मंडल के सदस्यों के लिये यह बंधनकारी है कि वे निर्वाचन कार्यवाही में पूर्ण सहयोग दें ।

क. 23—मुख्य कार्यपालन अधिकारी :-

1		संस्था का एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा जो अधिनियम के या बनाये गये कर्मचारी सेवानियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त होगा । यह अधिकारी संचालन मंडल के अधीक्षण/नियंत्रण के अधीन रहते हुए संचालक मंडल द्वारा सोसायटी के कार्यकलापों का प्रबंधन करेगा ।
2		प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचालक मंडल का तथा उसके अधीन गठित उप समिति का पदेन सचिव होगा । उसकी शक्तियां निम्नानुसार होगी—
	ए—	मुख्य कार्यपालन अधिकारी दैनिक व्यवसाय, कारोबारी गतिविधियों, कार्यकलापों का संचालन, पर्यवेक्षण, नियमन एवं नियंत्रण करेगा । संस्था का संपूर्ण प्रशासकीय अमला तथा कर्मचारी उसके प्रशासकीय नियंत्रण में एवं पर्यवेक्षण में होंगे । वह उसे प्रदत्त अधिकारों में से अपने अधिकारों को अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों में प्रत्यायोजित कर सकेगा । किन्तु ऐसे अधिकार जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रत्यायोजन में प्राप्त हुए हैं

		उन्हें प्रत्यायोजित नहीं कर सकेगा ।
--	--	-------------------------------------

	बी-	संचालक मंडल या स्टाफ उप समिति द्वारा किये गये कर्मचारी संबंधी आदेश को प्रशासकीय रूप में जारी करेगा । इसमें कर्मचारी/अधिकारियों की सेवा समाप्ति, हटाने, आर्थिक दंड देने, अन्य प्रकार के दंड देने, विभागीय जांच के निर्णय में की गई कार्यवाही होगी ।
	सी-	किसी कार्य विशेष के लिये श्रमिक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवानियमों के अंतर्गत नियुक्त करना, उन्हें निलंबित करना, हटाना, बर्खास्त करना, आर्थिक दंड देना ।
	डी-	कर्मचारी/अधिकारी से कोई ऐसा कार्य जिसमें कि शासकीय प्रतिभूति आवश्यक है, तो ऐसी दशा में प्रक्रिया का पालन कर प्रतिभूति प्राप्त करना ।
	ई-	संचालक मंडल एवं उपसमिति द्वारा जो निर्णय लिये गये हैं उनका क्रियान्वयन करना एवं उनके निर्णयों पर आदेश जारी करना ।
	एफ-	संचालक मंडल की स्वीकृति से संस्था के व्यवसाय के संबंध में ऋण प्राप्त करना या व्यवसाय के सफल संचालन हेतु कार्ययोजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना एवं संचालक मंडल के निर्णय के आधार पर विधिक कार्यवाही संपादित करना ।
	जी-	संस्था के विरुद्ध लगायी गई समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाही एवं संस्था की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करना या इसके लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना । संस्था की ओर से न्यायिक कार्यवाहियां करना या संस्था के विरुद्ध प्रस्तुत की गई न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष समर्थन करना ।
	एच-	संचालक मंडल के निर्णय अनुसार शासन, सदस्य या अन्य पक्षों के मध्य ठेका, इकरारनामा, भागीदारी, सह-भागीदारी, संयुक्त उद्यम संबंधी कार्य करना । इसके लिये उपनियम, नीति बनाना और उसके अनुमोदन के पश्चात उसका क्रियान्वयन किया जाना ।
	आई-	संस्था की ओर से प्रबंधन के लिये आवश्यक इकरारनामे, दस्तावेज निष्पादित करना या इस संबंध में कार्यवाही किया जाना । चल-अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, इससे संबंधित दस्तावेज व अन्य कार्यवाहियां किया जाना ।
	जे-	संस्था की ओर से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण करना ।

	के-	चल-अचल संपत्ति प्रतिभूति के रूप में दस्तावेजों का गिरवी, पृष्ठांकन जैसे दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना ।
	एल-	संस्था द्वारा किये गये व्यवसाय अंतर्गत कोई राशि विलंबित हो तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना या समझौता कर उन्मोचित किया जाना ।
	एम-	संस्था की चल-अचल संपत्ति में सुधार(रिपेयर), पुनर्निर्माण, सुसज्जित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना ।
	एन-	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को छोड़कर अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण करना । उनके विरुद्ध विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
	ओ-	संचालक मंडल एवं उसके द्वारा गठित उपसमितियों की बैठक आहूत करना । सूचनापत्र जारी करना, कार्य सूची तैयार करना, कार्यवृत्त तैयार करना एवं कार्यवृत्त को प्रेषित करना ।
	पी-	संस्था की वार्षिक साधारण सभा बुलाना , इसके अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य योजना तैयार करना ।
	क्यू-	वित्तीय पत्रक तैयार करना एवं संचालक मंडल के अनुमोदन के पश्चात वार्षिक आमसभा से अनुमोदित कराया जाना ।
	आर-	संस्था पर प्रभावशील होने वाले सेवाकर, व्यवसाय कर, आयकर का यथा समय भुगतान करना एवं इस संबंध में होने वाली समस्त विधिक/न्यायिक कार्यवाही करना या उसमें पक्ष समर्थन करना ।
	एस-	संस्था का ऑडिट कराना ।
	टी-	संस्था के व्यापार, लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक का निरीक्षण करना, उसे ऑडिटर को उपलब्ध कराना ।
	यू-	अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये गये सुझावों एवं आक्षेपों पर टीप अंकित कर संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में पंजीयक/रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना ।
	वी-	बजटीय नियंत्रण रखना ।
	डब्ल्यू-	बजट में स्वीकृत की गई राशि के अंतर्गत कार्यालयीन उपयोग हेतु स्टेशरी, पुस्तकें, आकस्मिक व्यय, टेलीफोन, बिजली, रिपेयर एवं स्थायी संपत्ति के मेंटेनेंस को स्वीकृत करना या इस संबंध में अधिकार अपने अधीनस्थों को अंतरित करना ।

	एक्स-	वैधानिक दस्तावेजों जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, उपविधि, आमसभा/संचालक मंडल/उपसमिति की कार्यवाही पंजी, संस्था पंजी, अंशपूंजी पंजी आदि वैधानिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना या सुरक्षित रखवाना ।
	वाय-	स्थानांतरण के आदेश प्रदान करना ।

क. 24-लेखा परीक्षण :-

1		लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 58 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत वार्षिक लेखाओ की संपरीक्षा के लिये या संपरीक्षक या अनुमोदित सनदी लेखापाल में से कराया जाएगा ।
2		अंकेक्षक नियुक्ति के संबंध में अधिनियम/नियमों या पंजीयक द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया व अधिकारिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

क. 25-उपसमितियां :-

1		संस्था अपने कार्य निष्पादन के लिये संचालक मंडल और उप समितियों का गठन कर सकती है । ऐसी गठित की गई समितियों में संचालक मंडल के 2 निर्वाचित सदस्य, 1 पंजीयक प्रतिनिधि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व संस्था का वरिष्ठ अधिकारी जिससे संबंधित उपसमिति है वह पदेन सचिव होगा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव होंगे । इन समितियों में निर्वाचित दो संचालकों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा ।
2		गठित की गई समितियों के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का कोरम होगा । समिति आहूत किये जाने के लिये न्यूनतम 7 दिन का सूचनापत्र जारी किया जाएगा । समिति में प्रशासक नियुक्त किये जाने की स्थिति में समिति की अध्यक्षता प्रशासक द्वारा की जाएगी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव होगा ।
		<p>उपसमितियां-</p> <p>1- स्टाफ उप समिति</p> <p>2- भंडारकय उप समिति</p> <p>3- व्यवसाय संचालन समिति</p> <p>4- कय विकय समिति</p> <p>उपसमितियों के सदस्य-</p> <p>1- समिति के अध्यक्ष 1</p> <p>2- निर्वाचित संचालकों में से 2</p> <p>3- पंजीयक के प्रतिनिधि 1</p> <p>4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव 1</p> <p>कोरम-</p> <p>कोरम कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक का होगा ।</p> <p>सूचना-</p>

	बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।
--	--------------------------------------

क. 26—लेखा वर्ष :-

1	संस्था का लेखा वर्ष होगा जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा ।
---	--

क. 27—निधियां तथा लाभ का विनियोजन:-

1.	<p>अधिनियम की धारा 43 एवं धारा 43(क) के अंतर्गत लाभ का विनियोजन किया जाएगा जिनमें मुख्य रूप से रिजर्व फण्ड 25 प्रतिशत की सीमा तक, भविष्यनिधि, अवक्षयण, आयकर, राज्य/जिला सहकारी संघ को देय अभिदान,निधि 2 प्रतिशत की सीमा में, अन्य ऐसी निधियां जो संस्था के व्यवसाय के अनुरूप हों ।</p> <p>निधियों का विनियोजन सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या पंजीयक द्वारा निर्देशित किये गये बैंकों में किया जाएगा ।</p>
----	--

क. 28—साधारण सभा में मताधिकार :-

1	साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा ।
---	---

क. 29—कर्मचारियों की नियम एवं सेवा शर्तें :-

1	म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 55(1) के अंतर्गत कर्मचारी सेवानियम तैयार कर अनुमोदित कराया जाएगा । तदनुसार कर्मचारियों का नियमन-नियंत्रण होगा ।
2	म.प्र. शासन/केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में बनाये गये अधिनियम, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्यनिधि, बीमा प्रभावशील होंगे ।

क. 30—विवरणियां :-

1	म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के अंतर्गत विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी । जिसमें निर्धारित किये गये विषयों पर जानकारी दिया जाना बंधनकारी है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस कार्य के लिये संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत कर सकते हैं ।
---	--

क. 31—परिसमापन :-

1	संस्था यदि अपने निर्धारित उद्देश्यों के क्रियान्वयन में सफल नहीं है तो संस्था स्वयं या पंजीयक द्वारा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत उसे परिसमापन में लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत होगी ।
---	---

— — 0 — —